अनुलग्नक

सितंबर, 2023 माह के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर मासिक सारांश

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,884 शहरों / कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ + के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1191 शहरों को ओडीएफ + + और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापट्टनम, कराड़, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को वाटर + रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालयों को गूगल मानचित्र पर "एसबीएम शौचालय" के नाम से देखा जा सकता हैं।

iii. स्वच्छता ऐप महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा हैं, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उन्हें ऐप में दर्ज करा सकते हैं, ताकि नगर निगम द्वारा उनका समाधान किया जा सके।स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो कुल शिकायतों का 94% से अधिक है।

iv. <u>टीम एसबीएम-शहरी की जापान यात्रा</u>

एशियाई विकास बैंक संस्थान के साथ साझेदारी करते हुए एशियाई विकास बैंक द्वारा टोक्यो, जापान में 5 और 8 सितंबर, 2023 को आयोजित की गई 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पध्दतियां के सुदृढ़ीकरण और सर्कुलर इकोनोमी में पिरवर्तन पर प्रशिक्षण' में संयुक्त सचिव, एसबीएम ने एमओएचयूए अधिकारियों के साथ भाग लिया।

v. <u>स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ</u>

स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी और ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर '23 के बीच वार्षिक स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा श्री कौशल किशोर, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री की उपस्थिति में एसएचएस-2023 का शुभारंभ किया गया था।

इस कार्यक्रम में एसएचएस-2023 के लोगो, वेबसाइट और पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 'इंडियन स्वच्छता लीग (आईएसएल) 2.0', 'सफाईमित्र सुरक्षा शिवर' लोगो और 'सिटीजन पोर्टल' का भी शुभारंभ किया गया।

vi. <u>भारतीय स्वच्छता लीग 2.0</u>

आईएसएल स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों में युवाओं को शामिल करके बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट युवा आधारित इंटर-सिटी पहल है। आईएसएल के भाग के रूप में, शहर की टीमें स्वच्छता के चैंपियन के रूप में समुद्र तटों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ियों की उत्साहपूर्वक सफाई कर रही हैं।

शहरों ने आईएसएल 2.0 के लिए दिलचस्प सिटी टीम के नामों को चुना है, चुने गए टीम कप्तानों और राजदूतों सहित सर्वश्रेष्ठ शटलर पीवी सिंधु, प्लॉगमैन रिपुडमन बेवली, पेडलर स्वस्तीका गोश, रामवीर तंवर डिफेंडिंग चैंपियंस चंडीगढ़ चैलेंजर, हुंसुर हेरोस, विक्तामिंगपुरम, दांडेली स्वच्छता वॉरियर, कुश्तगी चैंपियंस और अर्सिकेरे आर्मी पंजीकृत करने में पहली टीमों में से थे।

II. <u>स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)</u>

i. 1,70,392 करोड़ रुपये की 7,934 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,11,042 करोड़ रुपये की 6,098 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

ii. सितंबर माह के दौरान 86 करोड़ रुपए की 46 अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

iii. <u>भारत स्मार्ट सिटीज कॉनक्लेव 2023</u>

स्मार्ट सिटी ने 26-27 सितंबर 2023 को इंदौर में **इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023** का आयोजन किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में शहरी विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञों, दूरदर्शी और नवप्रवर्तक एक साथ एकत्रित हुए। इस कॉनक्लेव से एक सक्रिय मंच मिला, जिसने शहरों को और अधिक स्मार्ट, अधिक टिकाऊ और रहने योग्य स्थानों में बदलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बढ़ावा दिया। इस कॉनक्लेव के मुख्य बिंदुओं में से एक बिन्दु व्यापक प्रदर्शनी का था, जिसमें भारत भर के **33 इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड** प्रतियोगिता (आईएसएसी) के पुरस्कार विजेताओं के सर्वोत्तम कार्य को प्रदर्शित किया गया था। **भारत के माननीय राष्ट्रपति** ने 27 सितंबर 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश के इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में **आईएसएसी 2022 पुरस्कारों** के विजेताओं को सम्मानित किया।

प्रदर्शनी स्थल का दौरा करने वाले गणमान्य व्यक्तियों में **भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,** मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी थे।

iii. <u>स्मार्ट शहरों में लेबलिंग कार्यनीति का कार्यान्वयन</u>

स्मार्ट सिटी मिशन ने अपने सभी हितधारकों, विशेष रूप से नागरिकों में जागरूकता, गर्व पैदा करने और जानकारी प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए एक लेबलिंग कार्यनीति तैयार की। अब तक, **21 स्मार्ट शहरों ने** लेबलिंग कार्यनीति के रूप में, विभिन्न परियोजना साइटों पर सिग्नेज, स्टैंडी आदि लागू कर दिए हैं। इन 21 स्मार्ट शहरों में **चंडीगढ़**, **हुबली- धारवाड़, पुणे, कोयंबटूर, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, अगरतला, मदुरै, झांसी, श्रीनगर, आगरा, उदयपुर, पिंपरी चिंचवाड़, वारंगल, सोलापुर, ग्वालियर, औरंगाबाद और सेलम आदि शामिल हैं।** सिग्नेज, पोस्ट और स्टैंडी आदि लगाने से मिशन परियोजनाओं से संबंधित जानकारी से लोग अवगत हुए हैं, जिससे भावी योजना तैयार हो रही है।

iv. <u>प्लेमेकिंग मैराथन 5 और कॉल फॉर प्लेमेकर्स</u>

प्लेसमेकिंग मैराथन 5.0: स्मार्ट सिटी मिशन ने अगस्त 2023 में प्लेसमेकिंग मैराथन 5.0 लॉन्च किया है, जिसमें 31 जनवरी, 2024 तक 100 स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक में से कम से **कम एक कम उपयोग वाले सार्वजनिक स्थान** को परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, स्मार्ट सिटी मिशन ने उन प्लेसमेकर्स के लिए एक रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है, जो सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ काम करना चाहते हैं।

v. <u>स्ट्रीट एंड पब्लिक स्पेसेस वर्कशॉप</u>

स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरी परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शहरों को सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए स्ट्रीट एंड पब्लिक स्पेसेस वर्कशॉप शुरू की है। मिशन ने श्रीनगर, पिंपरी चिंचवाड़- पुणे और कोहिमा में आयोजित होने वाली तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं की योजना बनाई है। **क्षेत्रीय सड़क और सार्वजनिक स्थान कार्यशाला 26-27 अक्टूबर 2023** को श्रीनगर में आयोजित की जाएगी।

vii. **मिशन में उल्लेखनीय प्रगति**

- शहरों को साक्ष्य-आधारित स्मार्ट गवर्नेंस में मदद करने के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) **100 स्मार्ट शहरों** में संचालित किए गए हैं।

- दक्षता लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग/साझेदारी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए **180 पीपीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं** और **28 परियोजनाएं लगभग 2,769 करोड़ रुपये** के निवेश के साथ प्रक्रियाधीन हैं।

- **1,089 जीवंत सार्वजनिक स्थान** (नदी/झील, पार्क और खेल के मैदान, और पर्यटन स्थल) **परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं**।

- शहरों को अधिक जीवंत और सुस्थिर बनाने के लिए **1,199 डब्ल्यूएएसएच परियोजनाएं और 588 स्मार्ट ऊर्जा परियोजनाएं** पूरी की गई हैं।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. आज की तारीख में, 77,640 करोड़ रुपये की अनुमोदित कार्य योजना से अधिक 83,147 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें अधिक राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 41,097 करोड़ रुपये की 5,060 परियोजनाओं के लिए कार्य पूरा कर लिया गया है और 41,767 करोड़ रुपये की 839 परियोजनाओं के लिए कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, लगभग 73,565 करोड़ रुपये का वास्तविक कार्य पूर्ण/चल रही अमृत परियोजनाओं में किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 95% वास्तविक कार्य पूरा हो गया है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (एएंडओई), सुधार प्रोत्साहन और 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना' और 25 चयनित शहरों में 'स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) पर उप-योजनाओं के तहत 39,974 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

IV. दीनदयाल अंत्योदय योजना / राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई / एनयूएलएम)

i. चालू वित्त वर्ष के सितंबर माह के दौरान 6,088 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए; 3,662 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया; व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 6,096 लाभार्थियों को ऋण के साथ सहायता प्रदान की गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 6,763 ऋण दिए गए।

V. प्रधान आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. स्थापना के बाद से, मिशन ने 1.19 करोड़ आवासों को मंजूरी दी है, जिनमें से 113.32 लाख आवासों निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिनमें से 77.10 लाख आवासों को पूर्ण/ सुपुर्द किया गया है।

ii. सितंबर, 2023 के महीने के दौरान पीएमएवाई (यू) के तहत 3,390.03 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

VI. आवास

i. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नागालैंड को छोड़कर रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ii. 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (नियमित - 27, अंतरिम - 05) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय और सिक्किम ने प्राधिकरण स्थापित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम - 04) (अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं)।

iv. 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों ने आरईआरए के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटों का संचालन किया है। *(अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर चालू करने की प्रक्रिया में हैं)।*

v. 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त किया है और 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त नहीं किया है।

vi. देश भर में आरईआरए के तहत 1,12,472 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 81,310 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हैं।

vii. पूरे देश में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,14,396 शिकायतों का निपटान किया गया है, जिनमें से 2,630 शिकायतों का समाधान सितंबर, 2023 के महीने में किया गया था। सितंबर, 2023 के महीने के दौरान 2,258 परियोजनाएं और 3,241 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत किए गए हैं।

viii. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य ने पहले ही एमटीए के पहले के मसौदे के आधार पर किरायेदारी अधिनियमों को अधिसूचित कर दिया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने किरायेदारी कानूनों को मॉडल किरायेदारी अधिनियम (एमटीए) के नवीनतम संस्करण के साथ संरेखित करें। असम किरायेदारी अधिनियम, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एमटीए के नवीनतम संस्करण की तर्ज पर असम राज्य में अधिनियमित किया गया है। एमओएचयूए मार्च, 2024 तक देश भर में एमटीए को अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में है।

VII. पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि)

i. पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि) के तहत, 86,21,901 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 70,89,380 सस्वीकृत और 65,75,504 संवितरण किए गए हैं।

ii. सितंबर, 2023 के महीने के दौरान मिशन के तहत कुल 90.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

VIII. सीपीडब्ल्यूडी

i. दिनांक 25 सितंबर 2023 को तुमकुरु, कर्नाटक में टाउनशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के निर्माण के लिए एचएएल और सीपीडब्ल्यूडी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।